प्रकाशनार्थ / प्रसारणार्थ

अगस्त से पहले ईंट–भट्ठों को स्वच्छतर तकनीक में परिवर्तित कर लें–उपमुख्यमंत्री

पटना 07.02.2019

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ईंट निर्माता संघ की ओर से आयोजित 'ईंट निर्माण हेतु स्वच्छतर तकनीक' विषयक कार्यशाला के उद्घाटन के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य के करीब 7 हजार ईंट–भट्ठों में 2 हजार स्वच्छतर तकनीक में परिवर्तित हो चुका है। शेष बचे ईंट–भट्ठों को इस साल अगस्त के पहले नई स्वच्छतर तकनीक में बदल लें। नई तकनीक अपनाने वालों को कोयला नीति 2007 के तहत अनुदानिद दर पर प्राथमिकता के आधार पर कोयला उपलब्ध कराया जायेगा। ईंट–भट्ठों के बकाये के निपटारे के लिए सरकार शीघ्र वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लायेगी।

श्री मोदी ने कहा कि ईंट–भट्ठों की समस्याओं पर विचार करने के लिए जल्द ही खनिज, श्रम, वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्ततन, पुलिस, वाणिज्यकर व परिवहन आदि विभागों की बैठक की जायेगी। अन्य राज्यों में ईंट–भट्ठों के संचालन के लिए क्या नियमावली अपनाई गयी है और बिहार में क्या कमी है, इसपर भी विचार किया जायेगा।

जीएसटी लागू होने के बाद बिहार के 3944 ईंट–भट्ठा निबंधित है। कम्पोजिशन स्कीम के कारण 2016–17 की 51 करोड़ की तुलना में 2017–18 में मात्र 5 करोड़ ही ईंट–भट्ठा संचालकों को टैक्स देना पड़ा है। ईंट–भट्ठा के लिए अलग से कम्पोजिशन स्कीम का मुद्दा जीएसटी कौंसिल में उठाया है, मगर इसे लागू करना पूरे देश की सहमति पर निर्भर करता है।

उन्होंने कहा कि 2017–18 में खनिज विभाग के तहत राज्य के 6043 ईंट–भट्ठे निबंधित थे तथा उनसे 45 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि 2018–19 में मात्र 25 करोड़ का राजस्व ही प्राप्त हुआ है।

नई तकनीक से संचालित ईंट–भट्ठों में 1 लाख ईंट पकाने में 20 टन की जगह मात्र 12 टन कोयले की जरूरत होगी तथा इससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। प्रदूषण की गंभीर चुनौती है। एनजीटी, राज्य व केन्द्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय सभी इस चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं। राज्य सरकार चाहती है कि ईंट–भट्ठे बेहतरीन तरीके से चले, इसमें सभी से सहयोग की अपेक्षा है।